भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
स्व0 जगन्नाथराव जोशी सभागार
(बेंगलूरू – कर्नाटक)
(12–13–14 सितम्बर – 2008)

आर्थिक प्रस्ताव

अन्य अनेक क्षेत्रों की तरह, आर्थिक क्षेत्र में भी संप्रग सरकार के शासन के गत चार वर्ष आम आदमी के लिए घोर कुप्रबंधन, गवाएं गए अवसरों प्रतिगामी नीतियों अशमित आपदाओं और अनंत कष्टों की गाथा बनकर रह गए हैं। राजग ने अपने पीछे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था छोड़ी थी। 2003–04 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.6 प्रतिशत थी। बाजार में हर उत्पाद बहुतायत से मिलता था। भारत एक घाटे की अर्थव्यवस्था से उबरकर आधिक्य की अर्थव्यवस्था में पहुंच गया था। 2002 में देश को रिकार्डिड इतिहास की भंयकरतम सूखा का सामना करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप उस वर्ष देश में गत वर्ष की अपेक्षा चार करोड़ टन खाद्यान्न का कम उत्पादन हुआ था। किन्तु उस समय सरकारी गोदामों में 6.5 करोड़ टन खाद्यान्न का स्टॉक मौजूद था। हम उस समय अपने लोगों को न केवल भरपेट भोजन जुटा सके बल्कि सरकारी स्टॉक से खाद्यान्नों को उदारतापूर्वक बाजार में लाकर कीमतों पर भी अंकुश लगा सके। वर्तमान वित्तमंत्री द्वारा जुलाई 2004 में प्रस्तुत किए गए प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण में इस तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया था, ''अर्थव्यवस्था विकास, मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन की दृष्टि से सुधारोन्मुख प्रतीत होती है। यह एक ऐसा संयोजन है जो सतत, बृहत्–आर्थिक स्थिरता के साथ विकास–संवेग को सुदृढ़ करने के लिए काफी गुंजाइश प्रदान करता है।'' यही वह बिन्दु है जहां संप्रग सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। जब तक राजग सरकार द्वारा प्रदान किया गया संवेग बना रहा तब तक देश की अर्थव्यवस्था द्रुतगति से बढ़ती रही। जैसे ही वह संवेग खत्म हुआ, विकास क्रम डगमगाने लगा तथा अर्थव्यवस्था समस्याओं से घिर गई।

अर्थव्यवस्था में आज अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा मुद्रास्फीति का फैलाव है और अर्थव्यवस्था पर इसका समग्र रूप में पड़ने वाला कुप्रभाव है। इस वर्ष संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के पहले पैरे में ही उल्लिखित है, ''विकास प्रवृत्ति में हुए निर्णायक परिवर्तन का यह भी अर्थ है कि शायद अर्थव्यवस्था उन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं थी जो द्रुत विकास के साथ जुड़ी होती हैं।'' यह स्वयं

सरकार द्वारा विफलता की स्वीकृति है। सरकार ने इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार क्यों नहीं किया? 2008–09 हेतु **इकोनॉमिक आउटलुक** पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने हाल में जारी की गई अपनी रिर्पोट में टिप्पणी की है कि मुद्रास्फीति 13 प्रतिशत तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और इसमें 7 प्रतिशत तक कमी होने के लिए लम्बा समय, ठोस प्रयास और अनुकुल कारक होने चाहिए। **वर्तमान** संप्रग सरकार, जोकि इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है, के उलट राजग सरकार की एक महान उपलब्धि यह रही कि उसने मूल्यों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखा था। वर्तमान मूल्यवृद्धि का सर्वाधिक दुःखद पहलू आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनियंत्रित उबाल आना तथा उनकी आपूर्ति का कम हो जाना है। संप्रग शासन के दौरान खा़द्य सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ गई है। उसकी उगाही नीति विफल रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ है तथा आम आदमी के पास भूख से मरने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। देश के कई भागों – विशेषकर पश्चिम बंगाल में खाद्य उपद्रव भड़क उठे हैं। वहां पर वामदलों का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया है। संप्रग सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा का यह सीधा परिणाम है।

अपने दावों के विपरीत, संप्रग सरकार न केवल आम आदमी–विरोधी बल्कि किसान–विरोधी भी रही है। इस सरकार ने कृषि के आधारभूत ढांचे की पूरी तरह उपेक्षा की है। कृषि के बारे में सभी निवेश–लागतों में इजाफा हो गया है। उर्वरक के क्षेत्र में संकट व्याप्त है। उर्वरकों की आपूर्ति न केवल कम मात्रा में है बल्कि राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से इसकी आपूर्ति बढ़ाने के बारे में की गई अपीलों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उर्वरक के बारे में दंगे होना आम बात हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने 2015 तक कृषि उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, किन्तु ऐसा होने के कोई संकेत नहीं है क्योंकि कृषि उत्पादन अवरूद्ध बना हुआ है तथा वह मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है।

लाभकारी मूल्यों के प्राप्त न होने, समय पर चुकता किया जा सकने वाले और पर्याप्त उधार के न मिलने तथा ब्याज दरों में वृद्धि होने से गरीब किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। संप्रग शासन के विगत चार वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में कम से कम पांच हजार किसानों ने आत्महत्याएं की है। प्रधानमंत्री का किसानों के लिए बहु–प्रचारित 'विदर्भ–पैकेज' अन्–आरंभक (Non-Starter) साबित हुआ है। यही स्थिति किसानों के लिए ऋणमाफी योजना की भी है जिसने किसानों में रोष और असंतोष पैदा कर दिया है।

धान उगाने वाले किसानों कि यह मांग कि उन्हें गेहूं उगाने वाले किसानों के समान समझा जाए पूरी तरह न्यायोचित है। भाजपा धान की कीमत एक हजार रूपये प्रति क्विंटल तय किए जाने की पूरी तरह पक्षधर है। मगर सरकार इस मुद्दे पर लगातार सोई हुई है।

संप्रग सरकार ने किसानों की परेशानियों को भारी मात्रा में और ऊंची कीमत पर खाद्यान्नों का आयात करके और अधिक बढ़ा दिया है। राजग शासन के दौरान जो देश विशुद्ध रूप से निर्यातक रहा था उसे संप्रग सरकार ने अभागा खाद्य आयातक देश बनाकर छोड़ दिया है। गेहूं आयात में इस सरकार ने भारी घोटाला किया है। । गेहूं को न केवल ऊंचे मूल्य पर आयातित किया गया बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी सौदेबाजी की गई। सरकार ने ऐसे गेहूं का आयात किया जो मानव उपभोग के योग्य नहीं था।

संप्रग सरकार द्वारा अपनाई गई वर्तमान नीतियों से मूल्यों पर काबू पाने में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। भाजपा का विश्वास है कि जब तक राजस्व संबंधी मुद्दें और आपूर्ति संबंधी रूकावटें दूर नहीं होती हैं तब तक केवल मौद्रिक उपाय काफी नहीं होंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद तक ने उल्लेख किया है, ''अर्थव्यवस्था आपूर्ति संबंधी रूकावटों की शिकार है जो सबसे अधिक बिजली, सिचांई तथा पेयजल, सड़क तथा रेल परिवहन और शहरी तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे भौतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सबसे अधिक है।'' यह देखकर निराशा होती है कि राजग शासनकाल के दौरान इन क्षेत्रों में शुरू किए गए सर्वाधिक अच्छे कामों को या तो छोड़ दिया गया है या धीमा कर दिया गया है। बुनियादी ढांचे के मुहाने पर इस सरकार की एक भी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है।

मुद्रास्फीति के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रहने पर, संप्रग और उसकी अध्यक्षा ने आरोप लगाने का खेल खेलना शुरू कर दिया है। वे अर्न्तराष्ट्रीय कारणों–जैसे उच्च पेट्रोलियम क्रूड तथा सामग्री मूल्यों पर इसके लिए आरोप लगाते है; वे राजग शासन और उसकी नीतियों पर आरोप लगाते हैं– मानो इन नीतियों को बदलने के लिए सरकार के पास चार वर्ष काफी नहीं थे; वे जमाखोरों, कालाबाज़ारियों और मुनाफाखोरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई न करने के लिए राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हैं; वे व्यापारियों तथा व्यवसायी समुदाय पर आरोप लगाते है। वस्तुतः वे अपने आप को छोड़कर सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं। सौभाग्यवश, भारत के लोगों ने इन सब नाटकबाजियों को भांप लिया है तथा राज्यों में हुए एक के बाद एक चुनावों में संप्रग सरकार को अच्छा सबक सिखा दिया है और भारत के लोग आगामी आम चुनावों में उन्हें सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं।

जैसीकि आशा थी, उच्च मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरें भी ऊंची हो गई। सकल घरेलू उत्पाद में आई कमी जो गत वर्ष की इसी तिमाही की 9.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर इस वर्ष की तिमाही में 7.9 प्रतिशत रह गई है, का प्रमुख कारण मांग में कमी आना रहा है। गत वर्ष का 10.9 प्रतिशत का विनिर्माण विकास घटकर 5.6 प्रतिशत रह गया है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि तथा सेवा में भी महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई है। इसकी झलक परियोजना निवेशों में कॉरपोरेट द्वारा कटौती किए जाने में भी मिल रही है। सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हेतु नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उन परियोजनाओं की संख्या जो 31 मार्च 2008 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान या तो त्याग दी गई है या स्थगित कर दी गई है, गत वर्ष की 16 की तुलना में इस वर्ष यह बढ़कर 39 हो गई है। इसी प्रकार गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 45,925 करोड़ रूपये के निवेश वाली 184 परियोजनाओं की तुलना में 2007–08 की पिछली तिमाही के अन्त तक 13,456 करोड़ रूपये के निवेश वाली केवल 64 परियोजनाएं पूरी की गई थीं।

बढ़ती हुई ब्याज दरों ने मध्यम वर्ग के लोगों को दोहरी चपत लगाई है। एक ओर बढ़ती कीमतों के फलस्वरूप उनकी बजटीय गणना पटरी से उतर गई है, दूसरी ओर उन्हें उस ऋण के लिए **इक्वेटिड मंथली इंस्टॉलमेंट्स** के रूप में 35 से 40 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करना पड़ेगा जो उन्होंने घर निर्मित करने, फ्लैट या अन्य उपभोग्य सामग्री क्रय करने के लिए लिया होगा। इसके कारण मध्यम वर्ग को असहनीय कष्ट पहुंचा है।

कदाचित् अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन कहीं पर भी इतना अधिक जाहिर नहीं है जितना राजकोषीय मोर्चे (Fiscal Front) पर है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने टिप्पणी की थी, ''कृषि ऋणमाफी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना और छठें केन्द्रीय वेतन आयोग पर अमल से पैदा होने वाली गैर–बजटित (Unbudgeted) देनदारियों के साथ–साथ उर्वरक, खाद्य तथा तेल पर बढ़ती हुई ऑफ–बजट देनदारियों से पैदा होने वाले गंभीर वित्तीय खतरे मौजूद हैं। ये देनदारियां 2008–09 में 2.5 प्रतिशत के बजटित केन्द्रीय राजस्व घाटे से ऊपर जाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।'' यह और कुछ नहीं है बल्कि राजस्व संबंधी धोखा है। आर्थिक सलाहकार परिषद ने आगे कहा है कि '' ऑफ–बजट देनदारियों के साथ समस्या यह है कि न केवल वे अतिरिक्त भार आरोपित करती हैं जिसे देनदारियों के परिपक्व होने के समय निर्वापित करना पड़ता है बल्कि उनमें एक ठोस सर्विसिंग लागत निहित है।'' वित्तमंत्री का दावा है कि उन्होंने न केवल एफ. आर. बी. एम. एक्ट के लक्ष्यों को बनाए रखा है बल्कि वास्तव में उन्होंने उनसे भी ऊपर जाकर सुधार किया

है। क्या वे ऐसा मानतें है कि भारत के लोग अन्धे या अशिक्षित हैं कि वे इस खेल के पार तक नहीं झांक पाएंगे? वित्तमंत्री ने बड़ी चालाकी से इस वर्ष 3 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा समाप्त कर दिया है। यदि यह बड़ी हुई सब्सिडी या छठे वेतन आयोग का भार या किसान ऋणमाफी या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर हुआ अधिक व्यय है तो उनका रटा–रटाया उत्तर यह है कि उनके पास इन खर्चों को पूरा करने के लिए 0.5 प्रतिशत की गुंजाइश है। सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत लगभग 25,000 करोड़ रूपये होता है, अकेले 5 प्रतिशत ऑफ–बजट देनदारियां 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये की हैं। बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति और इसे नियंत्रित करने में सरकार की विफलता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। सकल घरेलू उत्पाद के 7.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे तथा 6 प्रतिशत के राजस्व घाटे के चलते, इस सरकार ने राजग शासन द्वारा सरकारी वित्त व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए किए गए सभी उपायों को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। बढ़ती हुई ब्याज दरें भारत सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के ब्याज–भार को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी, जिससे राजकोषीय गड़बड़ और बढ़ जाएगी।

संप्रग सरकार ने अपने वित्तकोषीय भार को भावी सरकारों को हस्तांतरित करने की प्रवृत्ति दर्शाई है – चाहे यह किसानों की ऋणमाफी हो या छठें वेतन आयोग की बकाया राशि हो, सरकार ने इस भार के अधिकांश भाग को खुशी–खुशी अगले वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाते समय सरकार ने बकाया राशि के इस वर्ष केवल 40 प्रतिशत तथा अगले वर्ष 60 प्रतिशत भुगतान का निर्णय किया है। अब खबर आई है कि पूरी 100 प्रतिशत बकाया राशि पर आयकर वर्तमान वर्ष में ही वसूल किया जाएगा। इस प्रकार किसी भी सरकारी कर्मचारी को न केवल कोई रकम नहीं मिलेगी बल्कि अगले आम चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली सरकार को ही 60 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान करना पड़ेगा तथा आयकर वसूली को भी गंवाना पड़ेगा।

भारी राजकोषीय घाटे बढ़कर करंट एकांउट तक भी पहुंच जाते हैं। यह तथ्य देखकर चिंता हो गई है कि करंट एकांउट घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ गया है जो 1.5 से लेकर 2 प्रतिशत तक की 'कम्फर्ट जोन' से कहीं ज्यादा है। यह उल्लेखनीय है कि राजग शासन के दौरान भाजपा ने करंट एकाउंट को इसके 30 वर्ष तक घाटे में रहने के पश्चात् सरप्लस में ला दिया था। इस लाभ की स्थिति को भी गवां दिया गया है।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य का अन्य चिन्ताजनक पक्ष घरेलू बचतों में प्रत्याशित ह्रास है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कथनानुसार सब्सिडी–भार की वृद्धि का सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों पर कुप्रभाव पड़ेगा। कॉरपोरेट मार्जिन के ह्रास से सापेक्ष प्राईवेट कॉरपोरेट बचतों की कमी में सहायता मिलेगी। घरेलू सेक्टर बचत के 2005–06 में सकल घरेलू उत्पाद के 24.2 प्रतिशत तक बढ़ने के पश्चात् इसमें तभी से कमी दर्ज हुई है। ऐसा विश्वास है कि 2002–03 के बाद से उच्चतर सकल घरेलू बचत उस वृद्धि के लिए जिम्मेदार है जो हमको हाल के वर्षों में देखने को मिली है। यदि सकल घरेलू बचतें अवरूद्ध होती हैं या घटती हैं तो इसका विकास पर कुप्रभाव पड़ना लाज़मी है।

सरकार द्वारा वर्तमान मूल्यवृद्धि के लिए बताया गया अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण–अर्थात् क्रूड ऑयल का उच्च अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अब लागू नहीं होता है। अब क्रूड की कीमत लगभग 150 अमेरिकी डॉलर से घटकर 100 डॉलर तक आ गई है। मगर पैट्रोलियम मंत्री रोज़ाना बयान दे रहे हैं कि पैट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम नहीं की जाएगी। भाजपा मांग करती है कि आम आदमी को कुछ राहत देने के लिए पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को तत्काल प्रभाव से कम किया जाए।

यह हैरत की बात है कि तेल आयातों की घटी हुई लागत के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूपये का मान कम होता जा रहा है। भाजपा महसूस करती है कि सरकार की पूरी शह और आर्शीवाद पाकर हेरा–फेरी करनेवाले स्टॉक मार्किट की तरह ही एक्सचेंज मार्किट में भी सक्रिय हैं।

भाजपा के लिए मुद्‌दा यह नहीं है कि इस वर्ष वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत या 7.5 प्रतिशत होगी। मुद्‌दा यह है कि इसके द्वारा पहले प्राप्त हुई 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत की कमी निरूपित होगी। मुद्‌दा यह है कि हम द्वि–अंकीय विकास की दहलीज़ पर पहुंचे हुए थे। वर्तमान सरकार द्वारा वह अवसर भी गंवा दिया लगता है। भाजपा के लिए मुद्‌दा यह है कि संप्रग सरकार के गत चार वर्षों में आम आदमी और किसानों ने अनकहीं मुसीबतें झेली हैं। इस सरकार ने किसान और आम आदमी के साथ भारी विश्वासघात किया है। राजग सरकार जिसने अपने उत्तराधिकारी को एक स्वस्थ और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की वसीयत छोड़ी थी, इसके विपरीत संप्रग सरकार अगली सरकार को पूरी तरह ध्वस्त अर्थव्यवस्था और भारी राशि के बिना भुगतान हुए बिल सौंपेगी।

बिहार में आई घोर आपदाकारी बाढ़ ने आपदा – कुप्रबंधन के मुद्‌दे को एकबार फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया है। 2002 में गुजरात के भूकम्प के बाद राजग शासन ने प्राकृतिक आपदाओं के खतरों का अनुमान लगाने, उनका प्रबंध करने और उसमें कमी

लाने के लिए कई संस्थाओं का गठन किया था। संप्रग शासन के अधीन इस प्रणाली पर जंग लग गया है। आपदाएं करोड़ों लोगों को कष्ट और विपत्तियां देने के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को भी सीधे प्रभावित करती हैं। भाजपा, भारत सरकार का आह्वान करती है कि वह आपदा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यचालन को युक्तिसंगत बनाए। भाजपा भारत के लोगों को यह आश्वासन भी देती है कि वह सत्ता में आने पर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी। यह अतिशय दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार के मंत्रिगण बिहार के लोगों के कष्टों का निर्लज्जतापूर्वक राजनीतिकरण कर रहे हैं और वे राहतकार्यों को मजबूत करने के बजाए राज्य सरकार के लिए रूकावटें खड़ी कर रहे हैं।

चार वर्ष तक वाम दलों के गुलामों की तरह व्यवहार करने और आर्थिक सुधारों के अग्रप्रयाण को न केवल रोकने बल्कि ध्वस्त करने के पश्चात् संप्रग सरकार अब अचानक सुधारों के महत्व के प्रति जागरूक हो उठी है और वह भाजपा के समर्थन से सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी। इससे पहले हमारी पार्टी ने जब कभी भी ऐसे विधानों के प्रति जो हमारे समय में उद्भूत हुए थे, समर्थन देने की पेशकश की थी, तब संप्रग सरकार उन पेशकशों को अवमानना सहित ठुकरा दिया करती थी। अब संप्रग भाजपा के समर्थन के लिए इतना उत्सुक क्यों है? भाजपा इन आर्थिक कानूनों को पारित करने के लिए अपना समर्थन देकर इस सरकार को खराब नहीं करेगी।

भारत के लोगों को यह मिथ्या विश्वास दिलाया गया था कि संप्रग सरकार आर्थिक नीति निर्माताओं की एक ऐसी सपनों जैसी टीम बनाकर सामने लाई है जैसी इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी तथा भारत एक निर्बाध समृद्धि, प्रचुरता और प्रफुल्लता के युग में पहुंचने वाला है। उस सपनों जैसी टीम द्वारा न केवल उस सपने को ध्वस्त किया गया है बल्कि इसने भारत के लोगों को एक त्रासद दुःस्वप्न दे दिया है।

संप्रग सरकार आर्थिक मोर्चे पर कभी कम न होने वाली आफत बन गई है। इस सरकार ने न केवल वाजपेयी युग में किए गए अच्छे कार्य को अकृत कर दिया है बल्कि इसने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया है जिन्हें आम आदमी–विरोधी, किसान–विरोधी, मध्यम वर्ग–विरोधी, कामगार–विरोधी तथा गरीब–विरोधी ही कहा जा सकता है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारत के लोगों का आह्वाहन करती है कि यदि वे अपने पेट में 'दाना' और अपनी जेब में 'आना' देखना चाहते हैं तो जब भी, जहां भी उन्हें अवसर मिलें, वे संप्रग और विशेषकर कांग्रेस पार्टी का तिरस्कार कर दें।

* * * * *